भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3322

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

18 श्रावण, 1945 (शक)

सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना

3322. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के विनिर्माण, डिस्प्ले पैनलों, विशिष्ट कलपुर्जी और आईसी की पैकेजिंग/परीक्षण जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई निधि सहित सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण के लिए प्रस्तावित 76,000 करोड़ रुपये की राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण में विश्वस्तरीय निर्यात उद्योग के निर्माण की संभावना को देखते हुए भारत में निर्यातोन्मुख चिप डिजाइन कंपनियों (कैबलेस कंपनियों) के विकास को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या पहल की गई है;

(ग) सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, विशेषकर अत्याधुनिक उत्पाद नवाचारों को डिजाइन करने के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजना का क्या ब्यौरा है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ शैक्षिक संस्थानों और निजी अनुसंधान संगठनों को सहायता और सहयोग देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) सरकार भारत के पहले से ही तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और नवाचार इको सिस्टम का और विस्तार करने के लिए समग्र सेमी कंडक्टर इको सिस्टम को गति देने के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको सिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं में 76,000 करोड़ रुपये का कुल राजकोषीय परिव्यय उपलब्ध है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, प्रदर्शन विनिर्माण और डिजाइन इको सिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा।

(ख) उपरोक्त कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं:

i. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने और एक विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करने में मदद करने के लिए देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए 'भारत **में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना '। यह योजना** भारत में सिलिकॉन सीएमओएस आधारित सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए *समान आधार* पर परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए देश में टीएफटी एलसीडी या एमोलेड आधारित डिस्प्ले पैनल के निर्माण हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए 'भारत **में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना '। यह योजना** भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए *समान आधार* पर परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

iii. भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसरफैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओसैट सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित स्कीम भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर्स (एमईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओसैट सुविधाओं की स्थापना के लिए सामान आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

iv. 'सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन: डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना' एकीकृत सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम एंड आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और तैनाती के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है। इस योजना में पात्र व्यय के 50% तक उत्पाद डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो प्रति आवेदन 15 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है और 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार का 6% से 4% का "परिनियोजन लिंक्ड प्रोत्साहन" प्रदान करता है, जो प्रति आवेदन 30 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है।

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, सरकार ने सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला, मोहाली को ब्राउनफील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

(ग), (घ) और (ङ) सरकार ने सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन: डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) स्कीम के अलावा उद्योग आधारित अनुसंधान एवं विकास, ट्रांसलेशनल अनुसंधान को बढ़ावा देने और उद्योग शिक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर स्किल चिप टू स्टार्टअप (सी2एस) कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया है।

****